



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 65

नवम्बर, 2020

अंक 11

कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

आशा है कि आप और आपके परिवार के सदस्य ठीक हैं। हमें पीएम मोदी के संदेश का पालन करना चाहिए, सावधान रहें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और हाथ धोएं। COVID लॉकडाउन के कारण, हम पिछले 7 महीनों से कृषक समाचार पोस्ट नहीं कर सके। लेकिन, अब हम पोस्ट कर रहे हैं। तीन विशिष्ट बिंदु नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बीच अंतर को दर्शाते हैं।



पीएम किसान के तहत, प्रत्येक भूमिहीन किसान (भूमिहीन को बाहर रखा जाता है) को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार, धान और गेहूं के संयोजन को विकसित करने वाला किसान प्रति एकड़ लगभग 50 लीटर डीजल का उपयोग करता है। डीजल का उपयोग फसल और प्रथाओं के आधार पर भिन्न होता है। आज, डीजल के प्रत्येक लीटर पर लगभग 45 रुपये का कर लगता है। भले ही देश में औसतन प्रति एकड़ देश में डीजल का उपयोग करने की छूट 60 प्रतिशत हो – 30 लीटर – सरकार वस्तुतः किसानों से प्रति एकड़ 1,200 रुपये का कर वसूल रही है। एक छोटे से पांच एकड़ के किसान को डीजल कर के रूप में लगभग 6,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है, जो कि लार्जस को प्राप्त हो रहा है।

दूसरा, जब जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 60 डालर प्रति बैरल थी, तब मेरे गाँव में वंचितों के लिए उज्ज्वला-योजना-सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 503 रुपये में उपलब्ध था। तब COVID-19 आया, प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, सरकारी राजस्व का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतें लगभग दो-तिहाई की कीमत 40 डॉलर पर स्थिर हो गई। जब सब कुछ नीचे की ओर बढ़ रहा था, इस जुलाई तक, सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत लगभग एक चौथाई से बढ़कर 611 रुपये हो गई। अविश्वसनीय रूप से, सरकार समाज के सबसे गरीब तबकों से प्रति सिलेंडर अधिक वसूल रही है, जब इसे लोकप्रिय रूप से

वित्तीय प्रदान करना माना जाता है उन्हें समर्थन। मोटे तौर पर, इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से प्रत्येक में आवर्ती विषय है – स्वयं गरीबों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

कई नीतियाँ प्रतिपक्ष हैं। उदाहरण के लिए, भारत में खपत होने वाली दाल का 75 फीसदी चना और अरहर हैं। दोनों एमएसपी से नीचे बेच रहे हैं, लेकिन मसूर दाल पर आयात शुल्क दो-तिहाई घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया क्योंकि भारत के एक हिस्से में इसके लिए मांग थी। मेरा मुख्य विवाद अधिक मौलिक है: यदि कोई उपभोक्ता अधिक महंगी दाल या अधिक महंगी गैर-आवश्यक उपज (जैसे, प्याज) खाने का जोखिम उठा सकता है, तो उसे फार्मगेट की कीमतों को कम करके सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रास्फीति को कम करने के दृष्टिकोण में एक रीसेट करना आवश्यक है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ग्रामीण भारत को उर्जा प्रदान करना : पश्चिम बंगाल राज्य का अनुभव

* सुजान पंडित

आज विश्व में फैली कुछ मुख्य समस्याओं के समाधान के रूप में सौर उर्जा के स्रोतों को कारगर ढंग से बढ़ाया जा रहा है। कार्बन आधारित पुराकालीन ईंधन के बुरे प्रभाव जैसे धरती की क्षमता का असंतुलन और वायु प्रदूषण बढ़ना (जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ना) के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए उर्जा के स्रोत बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, जैसे की सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा इत्यादि। इन स्रोतों से आम लोगों को एक रामबाण मिल रहा है और कई समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्योंकि इनके उपयोग से उपरोक्त दोनों बुरे प्रभावों को कम करने में सहायता मिल रही है।

आधुनिक, उर्जा स्रोतों के अन्य उपयोग यह हैं कि यह बिजली और उच्च गुणवत्ता की गरमी प्रदान करते हैं और खाना पकाने के साधन के रूप में भी उपयोग किये जाते हैं, तथा दूर-दूर के ग्रामीण क्षेत्रों, जिन्हें मुख्य ट्रान्समिशन ग्रिड से जोड़ना या तो बहुत कठिन है अथवा बहुत महंगा है, में कृषि कार्यों में सहायक होने के अतिरिक्त यह जलवायु को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन अलग-थलग क्षेत्रों के लिए यह उर्जा के स्रोत उत्तम ढंग से कार्य करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण भारत का अनिवार्य अंग है।

पश्चिम बंगाल अपने राज्य के दूर-दूर बसे क्षेत्रों में उर्जा के आधुनिक, नवीकरण स्रोतों का उपयोग करने में सबसे आगे है। इस राज्य में एक समस्या वैसी ही है जैसी भारत के अन्य

राज्यों में विद्यमान है किंतु एक प्रमुख अंतर है। बहुत से भारतीय राज्यों में उर्जा की कमी है और इस कारण कमी को पूरा करने के लिए नवीकरण उर्जा का उपयोग किया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बिजली का अधिक्य है। यद्यपि यह राज्य कोयला जैसे पुराकालीन ईंधन का उपयोग करता है तो भी इसकी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए यह राज्य पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। यदि बिजली वहां जाती भी है तो उसका कारण तार टूटना या ट्रॉंसमिशन ठप्प होना होता है न कि बिजली उत्पादन की कमी।

यदि पश्चिम बंगाल नवीकरण उर्जा का उपयोग करता है तो ऐसा करके यह कॉर्बन डाईऑक्साइड में कमी कर रहा है और उन एकांक क्षेत्रों में भी बिजली करा रहा है जहां से बिजली ट्रॉंसमिशन ग्रिड बहुत दूर होते हैं, चाहे इसका आर्थिक स्वरूप हो अथवा भौगोलिक कारण। पश्चिम बंगाल शत-प्रतिशत गांव और छोटी-छोटी बस्तियों को बिजली पहुंचाने की चुनौती का मुख्य कारण यह है कि इस राज्य में कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति काफी कठिन और दूभर है।

इस राज्य के 3 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुछ गांव और बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है, वे हैं;

1. सुन्दरबन के दूर-दूर स्थित कुछ गांव और बस्तियां (मुख्यतः साऊथ 24 परगना में)।
2. भारत-बांग्लादेश सीमा पर कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले में कुछ चाड़ क्षेत्र।
3. प्रमुख रूप में नेपाल-सिक्कीम सीमा पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर बसे कुछ गांव और बस्तियां।

उनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं ? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ? शेष भारत के लिए इनके क्या सीखा जा सकता है ?

सुन्दरबन

बंगाल की खाड़ी के समीप सुन्दरबन, गंगा डेल्टा क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मनुष्य द्वारा लगाए गए जंगल सबसे अधिक हैं और एक दूसरे को काटती हुई बहुत बड़ी-बड़ी नदियां भी हैं जिनकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक है। सुन्दरबन के दूर-दूर स्थित इन द्विपों को ट्रॉंसमिशन ग्रिड से जोड़ना और उनकी देखभाल करना अत्यधिक कठिन और महंगा है, यह क्षेत्र छितरे हुए स्थानों पर स्थित है जिसमें अलग-अलग स्थानों पर कुछ लोग ही रहते हैं।

इन क्षेत्रों के अधिकतम गांव बहुत निर्धन हैं और वे पारंपरिक उर्जा स्रोतों पर ही निर्भर हैं, जैसे कैरोसिन की लॉन्टेन का उपयोग रोशनी के लिए और कैरोसिन का ही प्रयोग खाना पकाने के लिए। किंतु पिछले 2 दशकों से स्थिति बदल रही है और लोग घरों में लाईट जलाने और

हवा तथा खाना बनाने आदि के लिए सौर उर्जा का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा कुछ सरकार एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे वैस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी अथवा लाभरहित संस्थाएँ जैसे रामकृष्ण मिशन, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इत्यादि। इन लोगों की बिजली की आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रमुख 3 आधुनिक नवीकृत उर्जा स्रोतों से पूरा किया जा रहा है:

1. बिजली के उत्पादन से और विकेन्द्रीकृत वितरित ग्रिड (डी.डी.जी.) अथवा माईक्रोग्रिड के माध्यम से उपलब्ध कराना : इन संयंत्रों के प्रत्येक संयंत्र में एक सौर फोटोवोल्टैक (एस.पी.वी.) 25 किलोवॉट और 120 किलोवॉट की बीच की क्षमता का या 200 और 500 किलोवॉट क्षमता के बॉयोमास गैसीफाईर से और लगभग 200-300 परिवारों को सीमित मात्रा (1 दिन में 5-6 घंटे के लिए 3 से 5 बत्ती अथवा पंखों को चलाने के लिए) में बिजली उपलब्ध कराने के लिए माईक्रोग्रिड के माध्यम से।
2. सौर होम लाईटिंग सिस्टम जिसमें सामान्य रूप से 1 सौर पैनल (20 वॉट से 120 वॉट की क्षमता), 1 बैट्री और 1 इन्वर्टर होता है। इन पैनलों को घरों की छतों पर रख दिया जाता है और उस घर में रहने वालों को सीमित बिजली मिल जाती है।
3. सौर लान्टेन : मिट्टी के तेल की लान्टेन जैसी दिखने वाली किंतु इस पर सबसे ऊपर एक छोटा सौर पैनल लगा होता है। यदि इसे दिन में धूप में रख दिया जाए तो यह इतनी बिजली उत्पन्न कर देते हैं जिससे रात को बिजली की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह बहुत सस्ती पडती है।

खाना बनाने के लिए ईंधन के मामले में अभी तक कुल निर्भरता लकड़ी जलाने पर है। कुछ स्थानों में बॉयोगैस प्लांट लगा दिए हैं जो आधुनिक चूल्हे जलाने में पर्याप्त मिथाईन उत्पन्न कर देते हैं।

पदमा नदी पर चाड़

इन चाड़ों में गंगा नदी के क्षेत्रों पर बसे कुछ छोटे गांव और बस्तियां शामिल हैं जिनसे भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री बनती हैं। यद्यपि नक्शों में इस क्षेत्र को चोड़ी-चोड़ी नदियों (विशेषकर पदमा नदी) से बनी बाउंड्री के रूप में दिखाया गया है, किंतु यह सच केवल मॉनसून में ही देखने को मिलता है। साल के बाकी समय के दौरान यह क्षेत्र पेड़-पौधों रहित नजर आता है और चारों तरफ रेत और धूल फैली नजर आती है जिसे वास्तव में एक मरुस्थल कहा जा सकता है। इस धूल भरे क्षेत्र के कुछ ऊपर कुछ गांव और बस्तियां हैं। यदि यहां बेहने वाली नदी के बहाव को बदलकर बड़े-बड़े ट्रांसमिशन ग्रिड बना दिए जाएं तो भी इस क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर स्थित बस्तियों के लिए यह व्यर्थ कार्य होगा।

चाड़ क्षेत्र के निवासी सुन्दरबन के निवासियों की तुलना में अधिक मात्रा में स्वदेशी स्रोतों पर विश्वास करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भ्रमण करने के लिए आने वाले लोगों और तस्करी कर अपनी आजीविका चलाने को देखते हुए अब सरकार ने इन लोगों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने पर कुछ ध्यान दिया है।

सुन्दरबन के क्षेत्र में तो बहुत से सरकारी नवीकृत उर्जा परियोजनाएँ और इससे संबंधित पहल की गई हैं, किंतु इस क्षेत्र के कुछ गांव में ही घर की बत्ती जलाने के लिए यह देखने को मिलता है किंतु गली की बत्ती आदि के लिए सौर उर्जा का उपयोग दिखाई नहीं पडता, यह कार्य भी कुछ परोपकारी संस्थाओं और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा नीजी रूप से वित्त देकर इस क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे की इन जिलों में भिन्न-भिन्न रामकृष्ण मिशन के कार्य चल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में धूल होने के कारण सौर पैनलों के रख-रखाव में बहुत कठिनाई आती है।

दार्जलिंग पहाडियां

उत्तरी बंगाल और दार्जलिंग पहाडियों के कुछ गांवों में बिजली की कमी है क्योंकि उनकी उंचाई समुन्द्र तल से बहुत अधिक है और दूर के स्थानों पर स्थित हैं, हालांकि यह प्रयास किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों को ग्रिड से जोड दिया जाए और इस कार्य को करने के लिए केन्द्रीय सरकार गोरखा लैंड क्षेत्रीय प्रशासन को राशि प्रदान कर रही है।

दार्जलिंग की पहाडियों और अन्य 2 क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएँ हैं : दार्जलिंग पहाडी क्षेत्रों में उंचे-उंचे पहाडों की जलवायु है और वहां तापमान बढ़ाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, विशेषकर पानी गरम करने के लिए। यहां पर ऐस.पी.वी. कम लाभकारी है क्योंकि यहां 12 महीने बादल छाए रहते हैं और धूप की कमी है, जबकि ऐसे स्थानों के लिए माइक्रो हाईड्रो या मिनी हाईड्रो अधिक उपयोगी उर्जा स्रोत हैं।

नेपाल अथवा सिक्कीम सीमा के आस-पास के कई गांव में भी अभी बिजली नहीं पहुंची है, विशेषकर सिंगालीला नेशनल पार्क और नियोरा घाटी नेशनल पार्क के गांव अथवा कुछ स्थान। सिंगालीना नेशनल पार्क में कुछ अतिथिग्रह और ट्रैक्स के हट्स स्थित हैं जिनकी छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनके साथ सौर उर्जा का सिस्टम घर की बिजली के उपयोग से जुडा हुआ है, इनका उपयोग अतिथिग्रहों में बिजली का उपयोग करने और ट्रैक्स के मोबाईल को रिचार्ज करने में किया जाता है। यह कठिन कार्य बहुत कम धूप होने के बाद भी और बिजली का उत्पादन करने की कम क्षमता होने के बाद भी किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण यहां बिजली इतनी महंगी है कि ट्रैक्स और अतिथियों से ये अतिथिग्रह रु. 50 से रु. 100 तक भी ले लेते हैं केवल उनके मोबाईल फोन को रिचार्ज करने के लिए।

धोतरे एक उदाहरण ऐसे गांव का जिसमें जून 2014 को बिजली नहीं थी और यह 8500 फीट से अधिक की उंचाई पर स्थित है और 51 एम.डब्ल्यू. रमाम हाईडल पावर स्टेशन की सडक पर स्थित है, यह पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामीत्व में है और उसी के द्वारा संचालित भी है।

इस राज्य के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने और कम धूप निकलने के कारण यहां कि पहाडियों में छोटे और सूक्ष्म जल संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, विशेषकर चाय बागानों में।

ग्रामीण बंगाल में डी.डी.जी. मॉडल के सामने आ रही समस्याएं

1990 के दशक के मध्य में जबसे पश्चिम बंगाल नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी स्थापित की गई है, तबसे पश्चिम बंगाल आधुनिक, नवीकरणीय उर्जा के स्रोतों का दूर-दूर के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने वाला अग्रणीय राज्य है। सुन्दरबन, जहां पर 1990 और वर्ष 2000 के बीच 1 मेगावॉट से अधिक क्षमता के संचित डी.डी.जी. बिजली के छोटे उर्जा संयंत्र बड़ी संख्या में स्थापित किये गये थे, में अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

किंतु समय बीतने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी डी.डी.जी. की पूरी पद्धति के सामने कई समस्याएं आनी शुरू हो गई। यह 2 प्रकार की हैं : समस्याओं के पहले सेट में तो यह कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने लगी, दूसरी इनके रख-रखाव की समस्याओं से संबंधित हैं। सुन्दरबन में 15 वर्ष पहले स्थापित किये गये विकेन्द्रीकृत माईक्रो ग्रिड बिजली वितरण सिस्टम में कई स्थानों पर ऐसी समस्याएं आई की इस पद्धति का उपयोग न के बराबर रह गया। इसका एक कारण यह है कि इनका संपर्क अधिकतम क्षेत्रों से किया गया जो सागर टापू में स्थित हैं। दूसरा, इनके टप्प होने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इन माईक्रो ग्रिड का कम चलना और उपयुक्त रख-रखाव न होना है।

बिजली वितरण नेटवर्क को दैनिक आधार पर चलाने और इसके बिल तैयार करने का प्रशासनिक ढांचा भी कमियों से भरा है जिस कारण यह बार-बार खराब होने लगा। वास्तव में कई मामलों में देखने में आया कि जिन गांव में बिजली नहीं थी वहां विकेन्द्रीकृत माईक्रो ग्रिड लगाने के कुछ समय के बाद पश्चिम बंगाल नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी इसे दैनिक आधार पर चलाने और बिल तैयार करने का प्रबंधकीय नियंत्रण स्थानिय पंचायतों या स्थानीय बिजली वितरण सहकारी संस्थाओं को सौंप देते थे।

यद्यपि पंचायत और सहकारी संस्थाओं द्वारा नियुक्त कर्मचारी अपने भरसक प्रयास करने के बाद भी इस कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने में नाकाम रहे, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान की कमी थी। दूसरी और पश्चिम बंगाल की सरकारी एजेन्सी द्वारा चलाए जाने वाले ग्रिड के संयंत्र जिन गांव में स्थापित थे वहां पर दैनिक समस्याओं और खराबी को दूर करने के लिए कुशल कार्मिकों का पूरा समूह था।

पंचायत और सहकारी संस्थाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के कारण कई बार द्वेष पूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिस कारण पूरा सिस्टम ही बदनाम होने लगा। प्रारंभ में तो बस्ती में रहने वाले लोग कम मात्रा में बिजली मिलने पर भी आभारी होते हैं, लेकिन समय बितने के साथ-साथ उनकी बिजली की मांग बढ़ती जाती है। अपनी मांग को पूरा करने के लिए वे अवैध ढंग से तारों में हुक डालकर बिजली की चोरी करते हैं, जिस कारण सीमित लोड होने के कारण वितरण कार्य में बार-बार खराबी आती है।

उर्जा भंडारण पद्धति लीड ऐसीड बैट्री आधारित थी, इस कारण एक 25 किलोवॉट के ऐस. पी.वी. पॉवर प्लांट के लिए पैदा की गई बिजली को स्टोर करने के लिए कई सौ बैट्रियों की आवश्यकता होती है।

- ◆ प्रथम, इतनी बड़ी संख्या में बैट्रियों को सही स्थिति में रखना एक चुनौती है।
- ◆ दूसरे, यदि बी.ओ.ऐस. के एलैक्ट्रॉनिक उपकरणों में कोई खराबी आ जाए तो स्थानीय कर्मचारी इसकी मरम्मत नहीं कर सकते। हालांकि वास्तव में उपकरणों की देखभाल का जिम्मा इन्हें देने वाले लोगों पर होता है, क्योंकि उनके ठेके में यह एक शर्त होती है, किंतु इस समस्या या खराबी को दूर करने में बहुत समय लग जाता है।

निष्कर्ष में कह सकते हैं कि गांव-वासी नियमित रूप से बिजली प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने बिजली के मासिक बिलों का भुगतान नहीं करते। उपभोक्ताओं से एक निर्धारित मासिक राशि ली जाती है जो उनके घरों में बिजली के पाईट की संख्या पर निर्भर करती है, न कि उन्होंने महीने में कितनी बिजली खर्च की उसकी यूनिट की संख्या पर, जैसा कि बिजली के व्यवसायिक कारोबारियों द्वारा मीटर लगाकर बिल भेजे जाते हैं

बिजली के बिलों का भुगतान न करने से पंचायत और सहकारी संस्थाओं को अपने संचालकों को मासिक वेतन देने में कई समस्याएँ आती हैं, जिस कारण बिजली संचालन में कार्य करने वाले कर्मचारी विमुख होकर अन्य कारोबार की और आमदनी की तलाश में चले जाते हैं। धीरे-धीरे उपकरणों की स्थिति भी खराब हो जाती है बार-बार बिजली जाना और जल्दी न आना जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को जूझना पड़ता है।

विकेन्द्रीकृत माईक्रो ग्रिड्स का भी बुरा हाल है क्योंकि वे दिन में केवल 5 से 6 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध कराते हैं, जबकि केन्द्रीकृत ग्रिड वाले बिजली की आपूर्तिकार 24 घंटे बिजली देते हैं। अतः जिन गांव में बिजली नहीं है वहां के वासी अपने क्षेत्रों में ग्रीड वाली बिजली चाहते हैं और उन्हें बिजली दी भी जा सकती है यदि वे अपने-अपने बिजली के बिल समय पर जमा कराते रहें।

इस समस्या का समाधान एस.पी.वी. पैनलों की गिरती लागत से आसान हो गया है जिस कारण ग्रामीणों और दूरस्थ रहने वाले लोगों को सस्ती दर पर बिजली देने की संभावना बनी है। उदाहरण के लिए सुन्दरबन में एक 25 किलोवॉट क्षमता के सौर माईक्रो ग्रिड बिजली संयंत्र की स्थापना 1 दशक पहले की गई थी, वह इसके आस-पास रहने वाले 250 घरों को 1 दिन में 5-6 घंटे बिजली देता है। यदि इस क्षमता को बढ़ाकर 25 से 100 किलोवॉट कर दिया जाए तो इन सभी घरों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है। पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसका कारण यह है कि 10-15 वर्ष पहले सौर पैनल बहुत महंगे थे, किंतु अब इस तकनीक में बड़ा परिवर्तन हो चुका है और यह सस्ती भी हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल में अभी भी डी.डी.जी. सिस्टम लगाने की संभावना है जहां कुछ गांव और बस्तियां केन्द्रीकृत बिजली ग्रिड से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में नवीकरणीय उर्जा उद्यमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जहां यह इन बिजली संयंत्रों को लगाकर और बिजली के मीटर के आधार बिल लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। 24 घंटे बिजली की नियमित आपूर्ति से डी.डी.जी. बिजली पर जो धब्बा इसकी विश्वसनियता पर लगा है, वह दूर हो सकता है।

नवीकरणीय उर्जा उद्यमी एक पुराकालीन ईंधन वाले उर्जा प्लांट की लागत पर ही एक नवीकरणीय उर्जा डी.डी.जी. बिजली का प्लांट लगा सकते हैं। इस कार्य को आरंभ करने में शुरू में जमा कराई जाने वाली राशि भी कम है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार नव एवम् नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के माध्यम से ऐसी योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।

इस उद्यम को स्थापित करके इसकी सफलता या असफलता की निर्भरता उस उद्यमी के उस क्षेत्र के स्थानिय ज्ञान पर है जो उसी आधार पर बिजली के सही बिल बनाए जितनी बिजली का उपयोग किया गया है और हुक डालकर या अवैध ढंग से बिजली की चोरी रोके तथा बिजली के तारों की कोई खराबी होने या बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उसका तत्काल समाधान करे।

*सदस्य, शासी निकाय, पश्चिम बंगाल नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी (डब्ल्यू.बी.आर.ई.डी.ऐ.)।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारत कृषक समाज ए-1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली- 110013, फोन: 011-24359509, 9667673186,
ई-मेल: ho@bks.org.in, वैबसाइट: www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित,
मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस -2, नई दिल्ली -110020 द्वारा मुद्रित।